THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Presumably, the question seeks information in regard to the Commissions of Inquiry set up by the Central Government to investigate into causes of communal riots in various parts of the country. No such Commission has been set up by the Central Government during the last three years.

(b) and (c) The recommendations of the various Commissions of Inquiry set up to investigate into the causes of communal riots in the country are kept in focus while formulating guidelines for combating communal violence and for promotoin of communal harmony which are periodically circulated to the various State Governments/U.T. Administrations for dealing with communal riot situations. Action against the guilty persons for specific offences listed in the Reports is taken under the law.

Complaints of frauds against high officials of State Bank of Indore

2981. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the then Chairman of State Bank Group, Central Office Bombay received a number of complaints from Members of Parliament regarding misappropriation/frauds committed by the high officials of the State Bank of Indore since January, 1988;

(b) if so, the number of complaints received by the Chairman/Managing Director/Deputy Managing Directors in this regard; and

(c) the action taken against the guilty officers of the State Bank of Indore?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Information is being collected, and to the extent available, will be laid on the Table of the House.

व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यात में वृद्धि करना

2982. **श्री शरद यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश का व्यापार घाटा कितना रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार घाटे के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार से ;

(घ) निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए जिन वस्तुओं की पहचान की गई है उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यातकों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता या रियायत प्रदान की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. आर. दासमुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का विदेशी व्यापार घाटा नीचे दिया गया है :

(मूल्य करोड़ रुपये)

वर्ष	व्यापार घाटा
1986-87	7644
1987-88 (पीआर)	6658
1988-89 (पी)	7412

पीआर : आंशिक रूप से संशोधित
पी : अनन्तिम

(ख) और (ग) चूंकि व्यापार घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 2.5% है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना कम ही है ।

(घ) निर्यात को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे--निर्यात के लिये उपलब्ध देशी माल की उपलब्धि बढ़ाना, प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतिस्पर्धी सामान के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर या लगभग उतनी ही कीमतों पर पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री को सुगमता से पहुंचाना तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्तीय तथा मौद्रक प्रोत्साहन प्रदान करना । विदेशी बाजारों में विशेष प्रयास के लिए अभिज्ञात किए गए फ्रस्ट क्षेत्र है : चाय विशेषरूप से पेकेज तथा मूल्यवर्धित रूपों में, अनाज विशेषकर गेहूं, संसाधित खाद्य जैसे फल तथा पेय, मांस और मांस उत्पाद तथा ताजे फल और सब्जियां; समुद्री उत्पाद, विशेषकर मूल्यवर्धित रूपों में, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़ा से बने सामान, इसमें बाद वाले पर अधिक जोर दिया गया है ; हस्तशिल्प तथा आभूषण, पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता टिकाऊ सामान में इलेक्ट्रानिक सामान तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर, आधारभूत रसायन, फैब्रिक, पीस-गुड्स तथा मेड-अप्स, सिलेसिलाए परिधान, ऊनी फैब्रिक तथा निटवियर, परियोजना और सेवाएं, तथा ग्रेनाइट ।

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यातकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और रियायतों में शामिल है : 100% निर्यात लाभों पर से आयकर छूट, रियायती दरों पर लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण, निर्यातकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 5% से 10% तक अंश के विदेशों में नर्यात कार्यकलाप बढ़ाने के लिए उपयोग की अनुमति, परियोजनाओं और परामर्शी सेवाओं से संबंधित निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक सहायता, निर्यातकों द्वारा भुगतान किए जाने वाली एजेन्सी कमीशन से सम्बन्धित मानदेयों को उदार बनाना, नकद मुआवजा सहायता, आदि ।

Cases of financial irregularities referred to the CBI by the State Bank of Indore

2983. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number of cases relating to financial irregularities referred to the CBI by the State Bank of Indore management during 1988 and upto July 1989?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): State Bank of Indore has reported that no case of financial irregularity was referred by it to CBI during 1988 and up to July, 1989.

Coverage of various categories under Group Insurance Scheme in Maharashtra

2984. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the progress made to cover the factory workers, the agricultural labourers and the farmers in Maharashtra under the Group Insurance Scheme during the last three years;

(b) the financial help extended under this scheme during the above period; and

(c) the targets, if any, set for 1989?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The progress of Group Schemes in the State of Maharashtra is as indicated by the following figures of new schemes introduced by the Life Insurance Corporation of India during the last 3 years:—

Year	No. of new Schemes introduced	No. of lives covered
1986-87 . . .	517	1,33,985
1987-88 . . .	777	1,24,282
1988-89 . . .	1054	1,74,022

(b) The number and amount of death claims paid under the LIC's Group Schemes